Toppersnotes
Unleash the topper in you

RAS

सामान्य अध्ययन पेपर-III

भाग-II

अर्थशास्त्र

SIERRA INNOVATIONS
Private Limited

अर्थशास्त्र

CONTENTS **PAGE NO.**

मांग और आपूर्ति	1-2
बैंकिंग	3-54
पूंजी बाजार	55-82
आर्थिक विकास	83-88
व्यापार नीती	89-91
मानव विकास सूचकांक	92-98
विदेश व्यापार नीति	99-116
विनिमय दर	117-123
विदेशी मुद्रा भंडार	124-151
वस्तु एवं सेवा (GST)	152-153
बजट (Budget)	154-172
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर	173-187
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	188-206

Toppersnotes
Unleash the topper in you

मांग = आपूर्ति

मांग > आपूर्ति (मुद्रा स्फीति)

मांग < आपूर्ति (आर्थिक मंदी)

उत्पादन के साधन :→ (1) भूमि → किराया
(2) श्रम → मजदूरी
(3) पूँजी → ब्याज
(4) उद्यमी → लाभ / factor cost

उत्पादन के सेक्टर :→ i) Primary sec.
ii) Secondary sec.
iii) Tertiary sec.
iv) quatesnary sec.
v) quinary sec.

	देशों	लोग	
कृषि सेक्टर	16%	50%	लगभग
उद्योग	30%	30%	
सेवा	54%	20%	
भौतिक			

Primary sec. → प्राकृतिक संसाधन से जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है
जैसे → कृषि, पशुपालन, खनन, वनउत्पादन, मत्स्यपालन

Secondary sec. → विनिर्माण और निर्माण को Secondary sec. में रखा है।
जैसे → टी.वी., पंखा, उद्योग में उत्पादित की गई वस्तुएं।

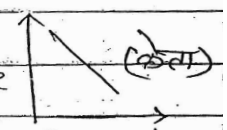
Tertiary sec. → सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है।
जैसे → Banking, education, health

quatesnary sec. → भौतिक सेवाओं को शामिल
जैसे → स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा

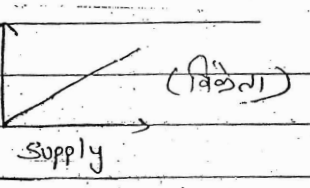
Toppersnotes
Unleash the topper in you

Quinary sec. → उच्च स्तरीय राजनैतिक और आर्थिक निर्णय से सम्बंधित सेवाएँ
- Ex. → प्रधानमंत्री, मंत्री, नौकरसा, CEO of companies, director

* Rule of Demand:→ कीमत और माँग (मुद्रा स्फीति) के बीच नकारात्मक संबंध होता है। कीमत ↑ तो माँग ↓



* Rule of Supply:→ कीमत और आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। अर्थात् कीमत ↑ तो आपूर्ति ↑



जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों ही शक्तियाँ संतुष्ट होती है। तो वस्तु की कीमत तय होती है।



* इन नियमों के अपवाद :→

(i) बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएँ
जैसे → नमक, मेडीसिन

(ii) Giffin Goods:→
कीमत बढ़ने पर घटिया वस्तुओं की माँग बढ़ती है।

गेहूँ	बाजरा
२० रु	१० रु.
३० रु./kg	१५ रु./kg

(iii) Veblen Goods:→
सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तुएँ, क्योंकि ये महंगी होती है इसलिए इनकी माँग होती है।
जैसे → महँगे क्लब की सदस्यता
फैशन से जुड़ी वस्तुएँ

Toppersnotes
Unleash the topper in you

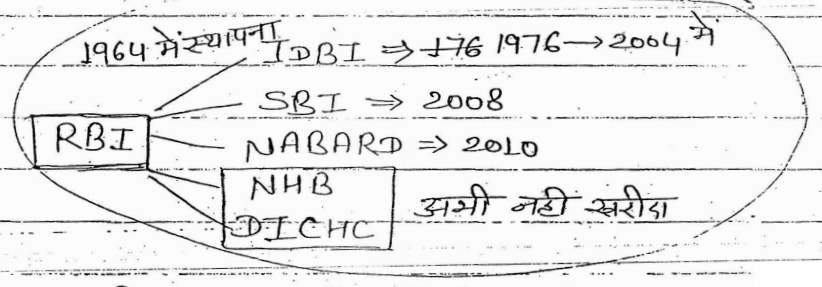
Banking ⇒ (i) 1770 ई. में Bank of Indo हिंदुस्तान पहला बैंक खुला।
(ii) 1881 ई. अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना। (भारतीय द्वारा संचालित पहला)
(iii) 1894 ई. PNB खुला था, यह पहला भारतीय बैंक था। (पूर्णरूपेण भारतीय बैंक)

History of SBI :⇒ 1840 में Bank of Bombay
1843 में Bank of Madras } → प्रजीडेंसी बैंक
1806 में Bank of Bengal

⇒ 1921 में तीनों बैंकों को मिला दिया गया और इसका नाम Imperial Bank of India
⇒ 1955 ई. में Imperial Bank of India का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे RBI के अधीन किया गया व इसका नाम SBI रखा गया।

⇒ 1959 ई. में रियासतों की जो बैंक थी इनको, उसकी की सहायक बैंक बना दिया गया। (पटियाला, बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, इन्दौर, हैदराबाद ये रियासत थी)
⇒ 1961 ई. में जयपुर और बीकानेर रियासत की बैंकों का नाम SBBJ कर दिया गया।
⇒ 2008 में सौराष्ट्र व 2010 ई. में इन्दौर को SBI में मिला दिया गया।

⇒ 2017 ई. में सभी को SBI में मिला दिया गया।
⇒ 5 बैंकों से SBI में विलय → बैंक of बीकानेर व जयपुर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर व त्रावनकोर
⇒ 2008 ई. में भारत सरकार ने SBI को RBI से खरीद लिया।



⇒ DFC → विकास के लिए वित्तीय संस्था

राष्ट्रीयकृत बैंक :⇒ 1969 ई. में इंदिरा गाँधी सरकार ने 14 बड़े Bank का राष्ट्रीयकरण जिन बैंको की 50 करोड़ से ज्यादा पूँजी (capital) थी उनका।

⇒ 1980 ई. में 6 और बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया।
⇒ 1993 ई. में New Bank of India का विलय PNB में कर दिया गया।

Q. भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन बैंको के विलय से क्या प्रभाव पड़ेगा।

* अनुसूचित बैंक :⇒ वे बैंक जिन्हे RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है, उन्हे अनुसूचित बैंक कहते है।
→ स्थापना के लिए 500 करोड़ के रूपये चाहिए।
→ इसपर RBI के नियम पूरी तरह लागू होते है।
→ ये RBI से सभी प्रकार की वित्तिय सहयता प्राप्त कर सकते है व चैक बुक जारी कर सकते है। ऋण देते है, debit card, credit card देते है।

कमर्शियल बैंक (वाणिज्यिक बैंक)	सहकारी बैंक
(1) ये संघ सूची का विषय है	(1) ये राज्य सूची का विषय है।
(2) ये एकस्तरीय ढाँचा होता है	(2) इनका त्रिस्तरीय ढाँचा होता है Apex Bank (राज्यस्तरीय) Central Bank (जिला) Co-operative (ग्राम पंचायत)
(3) इनका कार्य क्षेत्र निश्चित नही	(3) सहकारी बैंको का कार्य क्षेत्र निश्चित
(4) ये अनुसूचित बैंको की श्रेणी में आते है।	(4) अनुसूचित श्रेणी में नहीं आते
(5) इनकी शीर्ष संस्था RBI है।	(5) इनकी शीर्ष संस्था NABARD है।

भारतीय जीवन बीमा निगम → 1956, 1 Sept.

* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :→ (RRB) [Regional Rural Bank]
स्थापना - 2 अक्टूम्बर 1975 को हुई | (सिक्किम बगोग में छोड़कर)
इस समय केवल 5 RRB स्थापित किए गए थे | इसके बाद करीब 200 RRB स्थापित
जिनका उद्देश्य → ग्रामीण क्षेत्रों में Banking सुविधा उपलब्ध कराना |
→ ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कमर्शियल बैंक तीनों की भागीदारी से
स्थापित किया गया है | (60%) (20%) (20%)
⇒ अधिकांश RRB घाटे में चल रही है, अतः अन्य बैंकों में इनका विलय किया
जा रहा है |

RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) :→ स्थापना 1 अप्रैल 1935 ई. को
यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से
RBI अधिनियम 1934 से इसकी स्थापना की गई थी |
→ भारत सरकार अधिनियम 1935 ई. में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान
→ स्थापना के समय से ही यह एक केन्द्रीय व निजी क्षेत्र का बैंक था |
→ 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण
→ RBI ने कुछ समय तक पाकिस्तान व वर्मा के केन्द्रीय बैंक का कार्य किया |

RBI के कार्य :→ (1) नोटों का निर्गमन करना | 2 रुपये व उससे अधिक मूल्यों के
नोट जारी करता है |
(2) एक रुपये के नोट व सिक्के वित्तमंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं लेकिन इन्हें
बाजार में लाने का काम RBI करती है |
RBI द्वारा नोट छापना : → (i) ~~Reserve~~ Gold reserve system → इसमें नोटों
के बराबर सोना रखना पड़ता है |
(ii) Proposational Reserve System :→ नोटों के एक अनुपात में सोना रखते हैं |
(iii) minimum Reverse system :→ इसमें minimum सोना रखना पड़ता है |

(3) वर्तमान में RBI minimum Reserve system के तहत सोना जारी करती है | इसके तहत
200 करोड़ के न्यूनतम Reserve रखने पड़ते हैं | जिसमें 115 करोड़ का gold व 85 करोड़
की अन्य संपत्ति Reserve रखनी पड़ती है |

→ 1956 से RBI Minimum Reserve System अपनाया है।

(4) ये बैंको की विनियामक संस्था है। क्योंकि बैंको के लिए नियम और विनियम बनाता है। और उन्हे लागू करवाता है। जो बैंक नियमों का पालन नही करते उन पर ये कार्यवाही करता है। बैंको को लाइसेन्स देता है और रद्द भी करता है।

(5) ये सरकारी Bankes के रूप में कार्य करता है तथा भारत सरकार के लिए घरेलू ऋणो की व्यवस्था करता है।
इसके लिए भारत सरकार ने 2016 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत Public debt management cell का गठन किया।
यह एक सलाहकारी संस्था है व एक संक्रमण कारी संस्था है। क्योंकि कालांतर में Public debt management Agency का गठन किया जाएगा। जो कि भारत सरकार के लिए ऋणो की व्यवस्था करेगी।

(6) विदेशी मुद्रा भण्डारो का संरक्षण करना :- वर्तमान में RBI के पास लगभग 480 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भण्डार है। (अब → 392.80 अरब डॉलर)
विदेशी मुद्रा भण्डार निम्न है → (i) Foreign Assets → डॉलर, यूरो
(ii) Gold → सोना (iii) Reserve franche → Imf अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के पास
(iv) SDR (Special Drawing Right) [विशेष आहरण अधिकार] →
ये Imf द्वारा जारी किए जाते है व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भाँती उपयोग किया जाता है

(7) RBI रुपये की विनिमय दर का प्रबन्धन करती है। RBI बाजार मे हस्तक्षेप करके विनिमय दर को प्रभावित करती है।

(8) RBI बैंको को clearing house की सुविधा उपलब्ध करवाती है।
जहाँ RBI का कार्यालय नही है वहाँ RBI clearing house की सुविधा उपलब्ध करवाती है।

(9) बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है →

बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI दो तरह के उपाय करती है।

RBI

मात्रात्मक	गुणात्मक
Quantitative measures	Qualitative measures
(i) Bank Rate	(i) Margin requirment
(ii) CRR	(ii) Consumer credit regulation
(iii) SLR	(iii) Rationing of credit
(iv) Repo rate	(iv) Moral suasion
(v) Reserve Repo rate	(v) Direct Action
(vi) M.S.F. rate	
(vii) O.M.O	

Quantitative measures :→ (1) Bank Rate :→ वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंको को ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है। इसे Penal rate कहते है।

क्योंकि जो बैंक CRR को maintain नही करते है, उन पर यह दण्ड स्वरूप लगाई जाती है। क्योंकि ये Repo rate से अधिक होती है।

(2) CRR [Cash reserve ration] :→ (नगद आरक्षित अनुपात) सभी बैंको को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा कराना होता है या Cash reserve रखना होता है। यह आपात स्थितियों के लिए होता है। RBI इस पर ब्याज नही देता है, यह लम्बे समय से 5% है।

(3) SLR [Statutary Liquidity Ratio] :→ सभी बैंको को अपनी कुल देयता का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप मे रखना पड़ता है। सभी बैंको को अपनी कुल देयता का एक निश्चित % सरकारी Seqnity में निवेश करना अनिवार्य है। 20% सरकारी Seqnity लेना आवश्यक है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

LAF (Liquidity Adjustment facility):→ यह सुविधा RBI ने 2000 ई. में शुरू की इसके तहत Repo market विकसित किया गया है। ये नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर विकसित किया गया।
Full form of Repo→ Repurchase option (पुनर खरीद)
धन का विक्रेता एक निश्चित समय के बाद अपने धन को वापिस खरीदने का विकल्प अपने पास रखता है। इसमें सरकारी Security सुरक्षित रखी जाती है।
भारत में Repo market के तहत RBI और बैंको के बीच अल्पकालीन लेन-देन होता है।

Repo-rate:→ वह ब्याज जिस पर RBI बैंको को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है।

Reverse Repo-rate:→ वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपना धन RBI के पास जमा करवाती है।

M.S.F. Rate:→ [Marginal standing facility]:→ यह सुविधा RBI ने 2011 ई. मे शुरू की थी इसके तहत RBI बैंको को एक दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। यदि शुक्रवार को देती है तो यह तीन दिन के लिए होता है। ये CRR को बनाएँ रखने के लिए दिया जाता है। इसके तहत minimum एक करोड़ रुपये लेने आवश्यक है। यदि एक करोड़ से अधिक लेने हैं तो वेस अधि गुणक के रूप मे दिए जाते है। इसमे कुल जमाओ का 2%-तक ले सकते है।
Repo market के तहत बैंक को minimum 5 करोड़ लेने पड़ते है।
SLR के तहत रखी हुई Security को भी गिरवी रख सकते है।
जबकि Repo market के तहत SLR की Security को गिरवी नही रख सकते है।
यह सुविधा केवल मुम्बई में स्थित है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

Open Market Operation (O.M.O) :→ बाजार की तरलता को बनाएँ रखने के लिए RBI खुले बाजार की क्रिया का उपयोग करती है इसके तहत Security की खरीद या बिक्री करती है।
~~यदि~~ मुद्रा स्फीति की स्थिति में RBI Security की बिक्री करती है और मंदी की स्थिति में RBI Security खरीदती है।
O.M.O के तहत Security को खरीदा या बेचा जाता है।
जबकि Repo बाज़ार के तहत Security को निश्चित समय के लिए गिरवी रखा जाता है। इसलिए O.M.O दीर्घकालिक होता है। और Repo ~~market~~ अल्पकालिक होता है।
मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI ; Bank Rate, CRR, SLR, Repo rate, Reverse Repo-rate, M.S.F rate, O.M.O को बढाती है।
मंदी को नियंत्रित करने के लिए इन सबको कम करती है।

Qualitative measures :→ Margine Requirment :→ मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए margin money को बढाया जाता है।
मंदी के समय margin money को कम किया जाता है।

Consumer Credit Regulation :→ (down payment) मुद्रा स्फीति की स्थिति में down payment बढाया जाता है और मंदी की स्थिति में down payment कम किया जाता है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

Priority Sector Landing :→ [प्राथमिक ऋण क्षेत्र] → सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का (ऋण योग्य राशि) 40% प्राथमिक क्षेत्र में देना अनिवार्य है।

जैसे → कृषि → 18%

सीमान्त
आवास
शिक्षा
महिलाओं
SC/ST
वृहद् उद्योग
→ 22%

PSL CERTIFICATE :→ सन् 2016 में RBI ने बैंकों को PSL Certificate जारी करने की अनुमति दी। इसके तहत जो बैंक अपने लक्ष्य से अधिक प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देते हैं, वो इसके बदले में PSL certificate जारी कर सकते है। तथा जो बैंक प्राथमिक ऋण क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते वो ये Certificate खरीद सकते हैं।

CAPITAL ADEQUACY RATIO [CAR] पूँजी पर्याप्तता अनुपात :→ सभी बैंकों को अपनी जोखिम वाली परिसम्पतियों के एक निश्चित प्रतिशत पूँजी रखनी पड़ती है।
CAR का Concept BASEL मानकों से लिया गया है।

BASEL :→ [BANK FOR INTERNATIONAL SETTLMENT]
इसकी स्थापना 1930 ई. में हुई थी। ये केन्द्रीय बैंकों का संगठन है।
RBI 1996 में इसका सदस्य बना।
ये Banking क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान करवाता है और Banking क्षेत्र के विकास के लिए मानक जारी करता है जिन्हे BASEL मानक कहते हैं।

→ BASEL, स्विट्जरलैण्ड का एक शहर है। जहाँ इसका मुख्यालय है।
अब तक इसने BASEL I, II, III मानक जारी किये है।
→ BASEL-III मानक 2013 से 2019 तक लागू किए जा रहे है।
→ BASEL, मानकों का केन्द्रीय बैंक को मानना बाध्य नही होता है।
→ यदि RBI लागू करे तो Bank के लिए ये अनिवार्य है।

CALL MONEY MARKET :→ • ये अतिअल्पकालिक बाजार है, इसकी max. अवधि 15 दिन होती है।
इसमें सामान्यत: एक दिन के लिए loan लिया जाता है।

• रोजमर्रा के लेन देन के दौरान कुछ बैंको के पास Cash की कमी हो जाती है। जबकि कुछ बैंको के पास अतिरिक्त धन होता है।
इस स्थिति में बैंको में जो आपसी लेन-देन होता है उसे Call money market कहते है।
इसे Money of act Call भी कहते है।

• इसकी ब्याज दर Call rate कहलाती है। इसमें अत्यधिक उतार-चढाव होता है।
• Call rate को Refrence rate भी कहते है क्योकि केन्द्रीय बैंक इसके refrence से भावी मौद्रिक नीति निर्धारित करती है।
• लंदन विश्व का सबसे बड़ा Call money market है।
इसकी Call rate → LIBOR कहलाती है।

LIBOR → LONDON INTER BANK OFFER RATE

• भारत का Call money market मुम्बई है।
Call rate → MIBOR

MIBOR → Mumbai Inter Bank offer rate

Toppersnotes
Unleash the topper in you

* नरसिम्हन समिति → 1992 ई. *

→ बैंको का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए।
→ निजी सेक्टर की बैंको को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
→ विदेशी बैंको को भारत में बढावा देना चाहिए।
→ घरेलू बैंक और विदेशी बैंक में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
→ CRR और SLR को कम किया जाना चाहिए।
→ सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए।
→ NPA के लिए CIBIL (Credit information Bueno of India Limited) की स्थापना की जानी चाहिए।
→ Debt Recovery Tribunal (DRT) (ऋण वसूलीकरण न्यायाधिकरण) की स्थापना की जानी चाहिए।
→ ARC (Asset Reconstruction company) का गठन किया जाना चाहिए।
→ तीन तरह के Bank स्थापित किए जाने चाहिए →
(1) अंतर्राष्ट्रीय
(2) राष्ट्रीय
(3) स्थानीय

* नरसिम्हन समिति - II (1998) *

→ बैंको के आपसी विलय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
→ कमजोर बैंको का विलय मजबूत बैंको में नहीं किया जाना चाहिए।
→ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम करके 33% की जानी चाहिए।
→ LAF की सुविधा आरम्भ की जानी चाहिए और इसके तहत Repo market विकसित किया जाना चाहिए।
→ BASEL मानकों को अपनाया जाना चाहिए।

→ बैंकों के कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
→ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को और सहायता दी जानी चाहिए।

→ RBI से सरकारी बैंकर का कार्य ले लेना चाहिए।
→ NBFC को सरकारी दायरे में लाना चाहिए।
NBFC → (None Banking Finance Company)

* ऊर्जित पटेल समिति 2014 *

→ RBI का एक ही उद्देश्य होना चाहिए → Inflation (महँगाई) पर नियंत्रण।
→ RBI को अन्य मामलों में ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे →
① समृद्धि पर
② रोजगार के अवसर
③ निर्यात में वृद्धि
④ रुपये की विनिमय दर

→ target Inflation 4% रखी जानी चाहिए जो ±2% होनी चाहिए और अगले 2 वर्ष में नियंत्रण करना चाहिए।

→ WPI के स्थान पर CPI को मुख्य सूचकांक बनाना चाहिए।
WPI → whole sell price Index
CPI → Consumer Price Index

→ मौद्रिक नीति की समीक्षा 45 दिन से 60 दिन के अन्तराल में की जानी चाहिए।

→ समिति में 5 सदस्य होने चाहिए –
तीन RBI के → (1) गवर्नर
(2) उपगवर्नर
(3) कार्यकारी अधिकारी
2 सरकार के प्रतिनिधि होने चाहिए।

→ दो महीने के अन्दर इस कमेटी की बैठक होनी चाहिए।

→ समिति की कार्यप्रणाली में पूर्णतः पारदर्शिता होनी चाहिए। समिति कोई भी निर्णय बहुमत से देगी।

→ RBI का गवर्नर इस समिति का अध्यक्ष होगा, जिसके पास निर्णायक मत देने का अधिकार होना चाहिए।

→ सरकारी प्रतिनिधि किसी इसेर लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए।

→ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को ब्याज देय के निर्धारण के लिए सरकारी निर्देश नहीं देने चाहिए।

→ सरकार को अपने गैर योजनागत व्यय कम करने चाहिए।
अर्थात् सरकार को FRBM Act 2003 के लक्ष्य हासिल करने चाहिए।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

* मौद्रिक नीति समिति *

→ 2016 में संसद में अधिनियम पारित करके मौद्रिक नीति का गठन किया जाना चाहिए।
जिसमें 6 सदस्य होंगे → 3 सदस्य RBI → ① गवर्नर
② उपगवर्नर
③ कार्यकारी अधिकारी
तीन सरकार के प्रतिनिधि होंगे।

→ निर्णय बहुमत से लिए जाते है।

→ गवर्नर इसकी अध्यक्षता करता है तथा निर्णायक मत देने का भी अधिकार है।

→ गवर्नर के पास विशेषाधिकार नहीं है।

→ ३ महीने के अंदर इसकी कम से कम एक बैठक होनी चाहिए।

→ कार्यवाही में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी।

→ CPI को मुख्य सूचकांक बना दिया गया।

→ Target Inflation 4% रखी गई है। वह ±2% हो सकती है।

→ 60 दिन के अंतराल से यह कमेटी मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगी।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

बैंकिंग लोकपाल :→ RBI ने 1995 में स्थापना की।
देश के विभिन्न शहरों में 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए।
कार्य→ ये बैंक ग्राहकों की शिकायतों को सुनते है।

निम्न बैंक की शिकायतों को सुनते है → अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, NBFC (केवल ऋण से संबंधित)

बैंकिंग लोकपाल के समक्ष किस प्रकार की शिकायत ?
(1) छुपे हुए Charges (Hidden charges)
(2) समय पर Bank check व DD clear न होने पर
(3) बैंक खाता खोलने व बंद करने से इनकार करने पर
(4) ऋण देने से मना करने पर (योग्यता के बावजूद)
(5) सिक्के लेने से इनकार करने पर
(6) NET बैंकिंग से संबंधित

शिकायत नहीं की जा सकती →(1) 10 लाख से अधिक की शिकायत दर्ज नहीं
(2) 1 साल से पुराना केस दर्ज नहीं। (अब बढ़ाकर 20 लाख से अधिक)
(3) DRT के तहत विचाराधीन मामला → पहली शिकायत Branch manager के पास तथा 1 माह में सुनवाई न होने पर बैंकिंग लोकपाल के पास
(4) सामान्य शिकायतें

लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध ग्राहकों को अपील करने का अधिकार है जो कि RBI के उपगवर्नल के समक्ष की जाती है।
लोकपाल का विज्ञापन बैंकों मे लगाना आवश्यक है।